E-Learning Study Material
By Prof (Dr) YADWENDRA SINGH
MAHARAJA COLLEGE, ARA
VKS UNIVERSITY, ARA, BIHAR
BA. Part third Economics Hons
Paper VIth

New Deal Policy in America (USA) by President Roosevelt :-

4 मार्च 1933 को जब रुजवेल्ट ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया तो अर्थव्यवस्था की स्थिति अत्यन्त गंभीर एवं चिन्ताजनक हो गयी थी। 40 प्रतिशत उद्योग प्रायः समाप्त हो गये थे। किसान विद्रोह करने वाले हीं थे तथा हजारों की संख्या में बैंक दिवालिया हो गये थे। 25 प्रतिशत मजदूरी अर्थात् लगभग 140 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो गये थे। देश का निर्यात अपने न्यूनतम बिन्दु पर अपने न्यूनतम बिन्दु पर पहुंच गया था तथा बैंकिंग एवं साख व्यवस्था चूर चूर हो गयी थी। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक कार्य कलापों में सरकारी हस्तक्षेप की माँग कर रहा था।

रुजवेल्ट ने सत्तारूढ़ होते हीं सर्वप्रथम कार्य देश को आर्थिक संकट से मुक्त कराने की प्रक्रिया की शुरुआत की। इसके अपने

उसने अपनी कार्य योजना के उद्देश्यों इस प्रकार व्यक्त किया - "हमारा कार्य अभी उन साधनों और संस्थाओं का नियंत्रण करना है जो हमारे पास हैं। अतिरिक्त उत्पादन के लिए विदेशी बाजार प्राप्त करना तथा उपभोग, अर्द्ध उपभोग, धन और उत्पादन के समान वितरण की समस्याएँ बाद की बातें हैं।" यह कार्य निःसन्देह कठिन था लेकिन उसने तत्परता के साथ इसे व्यवहारिक रूप देने का निश्चय किया। 6 मार्च, 1933 को उसने कॉंग्रेस का एक विशेष आपातकालीन अधिवेशन बुलाया जो 16 जून तक चलता रहा। 6 मार्च को ही एक आपातकालीन घोषणा में उसने राष्ट्र भर में बैंक moratorium भुगतान स्थगन (moratorium की घोषणा की तथा स्वर्ण के जाते जाने पर रोक लगा दी। उसी दिन से स्वर्ण-मान को समाप्त कर दिया। कांग्रेस के इस अधिवेशन में देश के लिए वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक जीवन के सार्वकलापों के संचालन के लिए आवश्यक विधेयक स्वीकार किये गये। इस संबन्ध में पारित विधेयकों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:- प्रथम, तत्कालीन और आवश्यक समस्याओं से संबन्धित तथा द्वितीय, स्थायी उन्नति से सम्बन्धित। ~~इस प्रकार~~

इन दोनों प्रकार के विधेयकों को क्रमशः सहायता एवं पुनरुत्थान (Relief and Recovery) तथा सुधार और पुनर्निर्माण (Reform and Reconstruction) की संज्ञा दी गयी तथा इसे नया कार्यक्रम या न्यू डील (New Deal) का नाम दिया गया। इसका उद्देश्य अधिक टिकाऊ समृद्धि का निर्माण था।